

रिविजनल सिविल

समक्ष: मेहर सिंह, माननीय मुख्य न्यायधीश

मेजर माइकल ए. आर. स्किनर और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

नगरपालिका समिति, हांसी, - उत्तरदाता

1966 का सिविल संशोधन संख्या 240

15 मई, 1967

नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) - धारा 9-191.1 का पंजाब नगरपालिका अधिनियम उलफ) धारा 3 (1) (बीएफ (ii), 69, 84 और 86 - इस आधार पर गृह कर के रूप में वसूली गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए मुकदमा कि धारा 3 (एल) (बी) (ii) चाय के तहत कटौती की अनुमति नहीं है - चाहे सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य हो। यह माना गया है कि जहां शिकायत किसी कर के आकलन या लेवी के खिलाफ है या कोई कर लगाने से इनकार करने के खिलाफ है, तो यह पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (1) के तहत अपील का मामला होगा, लेकिन जहां शिकायत यह है कि कर उस पर लगाया गया है जो कर योग्य नहीं था, यह कराधान के मामले में प्राधिकरण के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का मामला होगा। अब, क्या छूट है और इसलिए कर योग्य नहीं है और जिसे वैधानिक कटौती के रूप में अनुमति दी गई है और जिसे उस राशि का हिस्सा

नहीं बनाया जा सकता है जिस पर कर लगाया जाना है, उसके बीच कोई पर्याप्त अंतर नहीं है। सार रूप में परिणाम एक ही आता है। इसलिए वर्तमान मामले में सिविल कोर्ट के पास आवेदकों के दावे की सुनवाई करने का अधिकार था, यदि यह सच है, क्योंकि प्रतिवादी नगर पालिका ने पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है क्योंकि उसने आवेदकों की संपत्ति पर करों के आकलन और लेवी के संबंध में अधिनियम की धारा 3 (एल) (; बी) (iii) को प्रभावी नहीं किया है ।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत हिसार के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश श्री बनवारी लाल सिंगला के दिनांक 14 जुलाई, 1964 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें श्री वीके कौशल, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, हिसार द्वारा वादी के वाद को खारिज करने की पुष्टि की गई है।

जी.सी मित्तल, याचिकाकर्ताओं के लिए, वकील।

बी. एस. गुप्ता, वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

मेहर सिंह सी.जे .-यह हिसार के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के 16 नवंबर, 1964 के अपीलीय फैसले से वादी का पुनरीक्षण आवेदन है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 15 अप्रैल, 1964 के फैसले और डिक्री की पुष्टि की गई है, जिसने वादी के मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 84 और 86 के तहत मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का उसका अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित है। 1911 (1911 का पंजाब अधिनियम 3), इसके बाद

एफसी को अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया।

मामले के तथ्य आवेदकों के वकील, श्री बाल कृष्ण जैन, अधिवक्ता, हांसी द्वारा अधिनियम की धारा 49 के तहत हांसी नगर पालिका के प्रशासक को 27 दिसंबर, 1 एस 63 के नोटिस में दिखाई देते हैं, और वादी द्वारा वाद में तथ्यों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। यह कहा गया है कि प्रतिवादी नगर पालिका ने हांसी में आवेदकों की संपत्ति के सकल वार्षिक किराये के मूल्य पर गृह-कर और जल-कर लगाया है और निम्नानुसार शुल्क लिया है: -

(१) 31 मई को 1,961 रुपये हाउस टैक्स के रूप में मिला;

(२) 31 मई, 1962 को हाउस टैक्स के रूप में 192 रुपये; 2 :

28

(३) 29 अगस्त, 1963 को हाउस टैक्स के रूप में 192 रुपये; और

(४) 13 नवंबर, 1963 को जल-कर के रूप में 108 रुपये।

फिर यह बताया गया है कि प्रतिवादी नगरपालिका ने अवैध रूप से 61.72 पैसे की वसूली की है। आवेदकों को राशि वापस करने के लिए दावा किया गया था। उस नोटिस पर आवेदकों द्वारा 61.72 पैसे की वसूली के लिए मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादी नगर पालिका ने एक संख्या ओ में प्रवेश किया? तीन बचाव सहित बचाव: -

(अ) यह कि अधिनियम की धारा 84 और 86 के मद्देनजर आवेदकों के दावे को राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से रोक दिया गया है:

(आ) वास्तव में धारा 3 (एल) (बी) (ii) के अनुसार सकल वार्षिक किराए पर 10 प्रतिशत मरम्मत की कटौती आवेदकों को अनुमति दी गई थी; और

(इ) आवेदकों के संबंध में मूल्यांकन आदेश उपायुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 84 के तहत आवेदकों की सहमति के साथ अपीलीय निगरानी का प्रयोग करते हुए दिए गए थे।

ट्रायल जज ने केवल प्रतिवादी नगर पालिका द्वारा उठाए गए बचाव में से एक पर विचार किया और यह अनुमान लगाया कि मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने के लिए यह अधिकार क्षेत्र है। यह आवेदकों के खिलाफ पाया गया और वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अपील पर इसकी डिक्ली की पुष्टि की गई है।

आवेदकों की ओर से यहां तर्क यह दिया गया है कि आवेदकों के दावे के बचाव में प्रतिवादी नगर पालिका द्वारा उठाए गए अन्य प्रश्नों को छोड़कर और सीमा के सवाल को छोड़कर, यदि यह भुगतान किए गए कर की किसी भी राशि के संबंध में उठता है, तो केवल एक मामला जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह वह है जो नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष तर्क के अधीन था - क्या सिविल कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र है या नहीं। आवेदकों के दावे का प्रयास करें?

आवेदकों के विद्वान वकील अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) (ii) को संदर्भित करते हैं, जिसमें लिखा है: -

"3 (1) 'वार्षिक मूल्य' का अर्थ है: -

(अ) * * * * *

(आ) किसी मकान या भवन के मामले में, सकल वार्षिक किराया, जिस पर ऐसा मकान या भवन, उसके भरण-पोषण और किसी भी फर्नीचर के साथ, जिसे उसके उपयोग या आनंद के लिए अनुमति दी जा सकती है, यथोचित रूप से निम्नलिखित कटौतियों के अधीन वर्ष-दर-वर्ष अनुमति देने की उम्मीद की जा सकती है: -

(ऐ) * * * * *

(ii) मरम्मत की लागत और अन्य सभी खर्चों के लिए 10 प्रतिशत की कटौती, जो इस तरह के सकल वार्षिक किराए को कमांड करने के लिए राज्य में भवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस उप-खंड के तहत कटौती की गणना उप-खंड (आईवी) के तहत कटौती के बाद सकल वार्षिक किराए की शेष राशि पर की जाएगी

और उनका तर्क यह है कि मरम्मत की लागत और सकल वार्षिक किराए के लिए राज्य में संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक अन्य सभी खर्चों के लिए 10 प्रतिशत की कटौती मूल्यांकन प्राधिकरण पर एक वैधानिक मांग है जिसका उसे अनुपालन करना चाहिए। यदि यह उस मांग का अनुपालन नहीं करता है, तो यह कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करता है और इसलिए दावा सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। विद्वान वकील एक कर कानून में प्रदान की गई वैधानिक कटौती की तुलना इस तरह के कानून में प्रदान की गई छूट से करता है। एक कर कानून में छूट कहती है कि कुछ चीज़ कर के लिए उत्तरदायी नहीं है और कर कानून में कटौती उसी पर आती है, क्योंकि यह इससे अधिक नहीं है, कि कर केवल कटौती से कम किसी चीज़ पर आकर्षित होता है। दूसरे शब्दों में, जो कटौती की जानी है, उस पर कर आकर्षित नहीं होता है। विद्वान वकील तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दो मामलों, *फर्म सेठ राधा किशन बनाम भारत का उल्लेख करते हैं। नगरपालिका समिति। लुधियाना (1)*, और *केरल राज्य बनाम केरलरामास्वामी अय्यर एंड संस (2)*, जिसमें लॉर्डशिप ने कहा है कि जहां एक कर लगाने वाला कानून अपने दायरे में शिकायतों के निवारण के लिए एक पूर्ण मशीनरी प्रदान करता है, तो कानून के तहत उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन, भले ही ऐसे मामलों के संबंध में अदालत के अधिकार क्षेत्र को

या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो, यह अभी भी अधिकार क्षेत्र है जहां कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है या 12 सांविधिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि नगरपालिका ने आवेदकों की संपत्ति के वार्षिक मूल्य का आकलन करने या करों को लागू करने और प्राप्त करने में न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। तर्क यह है कि इसने कानून का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि इसने मरम्मत की लागत और अन्य खर्चों के लिए 10 प्रतिशत की कटौती की अनुमति नहीं दी है जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) (ii) में उल्लिखित है। प्रतिवादी नगर पालिका के विद्वान वकील बताते हैं कि प्रतिवादी नगर पालिका के लिखित बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल्यांकन आदेश आवेदकों की सहमति से किए गए थे। हालांकि, यह एक ऐसा मामला है जो आवेदकों के दावे के लिए प्रतिवादी नगरपालिका द्वारा उठाए गए बचावों में से एक के गुण-दोष से संबंधित है। विचारणीय प्रश्न यह है कि जैसा कि पहले ही कहा गया है, क्या सिविल कोर्ट के पास आवेदकों के दावे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं?

'वार्षिक मूल्य' की परिभाषा अधिनियम की धारा 3 (i) में दिखाई देती है। धारा 61 उन करों से संबंधित है जो नगरपालिका द्वारा लगाए जा सकते हैं और इसके खंड (1) के उप-खंड (ई) का अर्थ है 'एक कर, जो किसी भी इमारत के कब्जेदार द्वारा देय है, जिसके संबंध में समिति के पास अधिनियम की धारा 159 से 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, है, '1 हाउस स्कैवेजिंग' का काम शुरू किया। एक नगरपालिका को अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के तहत एक प्रस्ताव पारित करना होता है और फिर इस धारा की शेष उप-धाराओं के

रूप में करों को लागू करने की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस धारा की उपधारा (12) कहती है कि 'इस अधिनियम के तहत कर लगाने की अधिसूचना निर्णायक सबूत होगी कि कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है। -

63. समिति एक आदेश का कारण बनेगी	कर की आकलन सूची किस पर तैयार की गई इमारतों और जो कोई भी भूमियों में शामिल हैं-हो	सूची किस पर लगाई जाती है?	सब
(क) *।	*	*	*
(ख) *	*	*	*
(ग) *	*	*	*
(ग) *	*	*	*
(ई) वार्षिक मूल्य, क्षेत्र या फ्रंटेज की लंबाई जिस पर संपत्ति का आकलन किया जाता है; और			

(उ) समिति द्वारा उस पर मूल्यांकन किए गए कर की राशि।

इस तरह की सूची विधिवत प्रकाशित की जाती है, और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार मूल्यांकन और मूल्यांकन पर आपत्तियां की जा सकती हैं। धारा 66 (1) आपत्तियों की जांच और मूल्यांकन सूची के अंतिम निपटान से संबंधित है, जिसकी इस धारा की उप-धारा (2) के अनुसार, सार्वजनिक नोटिस दिया जाना है कि यह निरीक्षण के लिए संपत्ति के सभी मालिकों और कब्जेदारों के लिए खुला है। धारा 67 मूल्यांकन सूची के संशोधन से संबंधित है, और धारा 68 हर साल ऐसी नई सूची तैयार करने से संबंधित है। धारा 69 वर्तमान मामले में कुछ हद तक प्रासंगिक है और इसमें लिखा है-

69. इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन किए गए किसी कर

के मूल्यांकन और किसी भी शुल्क या मांग पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के नाम, निवास, व्यवसाय के स्थान या व्यवसाय में किसी गलती के कारण या कर के लिए उत्तरदायी किसी संपत्ति या वस्तु के विवरण में महाभियोग या प्रभावित नहीं किया जाएगा। या मूल्यांकन या कर की राशि में किसी भी गलती की। या किसी लिपिकीय त्रुटि या फॉर्म के अन्य दोष के कारण; और यह संपत्ति पर ऐसे किसी कर में या ऐसे किसी कर के उद्देश्य के लिए मूल्य के किसी भी मूल्यांकन में पर्याप्त होगा यदि कर लगाया गया या मूल्यांकन किया गया संपत्ति को आम तौर पर ज्ञात बताया गया है: और उसके मालिक या कब्जेदार का नाम लेना आवश्यक नहीं होगा।

धारा 84 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 85 की उप-धारा (1) करधान के खिलाफ अपील और ऐसी अपीलों के लिए सीमा से संबंधित है। वे खंड हैं-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मूल्यांकन या लेवी के विरुद्ध या किसी कर की वापसी से इनकार करने के विरुद्ध अपील उपायुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी के पास होगी जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त करे:

परन्तु जब उपायुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी, जैसा कि पूर्वोक्त है, या जब कर लगाया गया था, समिति का एक दायित्व है, तो अपील राज्य सरकार के पास होगी। यदि, इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई के दौरान, किसी कर के दायित्व या मूल्यांकन के सिद्धांत के बारे में कोई प्रश्न उठता है, जिस पर अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी उचित

संदेह पर विचार करता है, तो वह या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या इच्छुक किसी व्यक्ति के आवेदन पर, मामले के तथ्यों और उस बिंदु का विवरण तैयार कर सकता है जिस पर संदेह पर विचार किया जाता है, और उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए बिंदु पर अपनी राय के साथ बयान का संदर्भ लें।

(पचासी) (1) किसी भूमि या भवन पर कर के संबंध में कोई अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसे धारा 66 या धारा 68 द्वारा निर्धारित नोटिस के प्रकाशन के एक महीने के भीतर या धारा 69 के तहत किसी अंतिम आदेश की तारीख के बाद, जैसा भी मामला हो, प्राथमिकता न दी जाए, और किसी अन्य कर के संबंध में कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि उसे मांग के समय से एक महीने के भीतर प्राथमिकता न दी जाए। कर के लिए बनाया गया है:

बशर्ते कि इस धारा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता उस अधिकारी को संतुष्ट करता है जिसके समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जाती है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

एकमात्र अन्य खंड जिस पर ध्यान दिया जा सकता है वह धारा 86 है। जो इस रूप में है-

(छियासी) (1) किसी मूल्यांकन या मूल्यांकन के संबंध में कोई विलंबति नहीं ली जाएगी और न ही मूल्यांकन या कर लगाए जाने वाले किसी व्यक्ति के दायित्व पर इस अधिनियम में उपबंध के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्न किया जाएगा।

(दो) इस अधिनियम और इसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कर की वापसी का दावा नहीं किया जाएगा।

धारा 86 की उपधारा (11) से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के मूल्यांकन या दायित्व के मूल्यांकन या कर के संबंध में, जो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, उस पर अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा सकता है, न कि किसी अन्य प्राधिकरण के माध्यम से, जिसमें स्पष्ट रूप से एक सिविल न्यायालय शामिल होगा। इसलिए धारा 86 की उप-धारा (1) के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अधिनियम के प्रावधानों के तहत मूल्यांकन या कर लगाए जाने वाले किसी भी मूल्यांकन या मूल्यांकन या दायित्व के संबंध में किसी भी अस्पष्टता पर विचार करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा

धारा 69 में प्रावधान है, जिसे पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है और इस मामले से संबंधित भाग में लिखा है-

"69. इस अधिनियम के अधिकार के तहत किए गए किसी भी कर के किसी भी मूल्यांकन और किसी भी शुल्क या मांग पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा या कारण से प्रभावित नहीं किया जाएगा *** *
 *
 मूल्यांकन या कर की राशि में किसी भी गलती के बारे में,
 *
 *"

अब, आवेदकों के विद्वान वकील बताते हैं कि यह धारा केवल एक गलती तक ही सीमित है और यह एक ऐसे मामले को कवर नहीं करती है जहां एक नगर पालिका, जैसा कि इस मामले में, अधिनियम की धारा 3 (एल) (बी) (ii) के अनुसार कटौती की अनुमति देने में पूरी तरह से विफल रही है या ऐसा करने से इनकार कर दिया है, हालांकि पहले से

ही पुनः प्रस्तुत किए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्द "किसी भी लिपिक त्रुटि या अन्य के कारण" दिखाई देते हैं। फॉर्म का दोष। मुझे लगता है कि आवेदकों के विद्वान वकील द्वारा दिया गया तर्क सही है। इस धारा के प्रावधानों को आकर्षित करने से पहले पहले गलती होनी चाहिए। यदि यह गलती का मामला नहीं है, तो यह धारा आकर्षित नहीं होगी। जाहिर है जहां कटौती कानून द्वारा की जाती है और यह मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है, यह केवल गलती का मामला नहीं है। यह अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करने का मामला होगा। हालांकि, प्रतिवादी नगर पालिका के वकील का तर्क है कि सबसे पहले यह एक गलती का मामला होगा और दूसरी बात यह है कि अधिनियम की धारा 3 (एल) (बी) (2) के तहत कटौती की अनुमति देना या ऐसा करने से इनकार करना एक ऐसा मामला होगा जो अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (1) के अनुसार अपील के अधीन होगा और "किसी के मूल्यांकन या लेवी के खिलाफ या किसी को भी वापस करने से इनकार करने के खिलाफ" होगा। इस अधिनियम के तहत कर * * * * * यद्यपि यह एक ऐसा मामला है जिसे अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (1) के तहत अपील में भी उठाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने धारा 3 (1) (बी) (ii) के रूप में वैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने में अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, जब वह इसे छोड़ देता है या इसे प्रभावी करने से इनकार करता है। ताकि जहां शिकायत किसी कर के आकलन या लेवी के खिलाफ हो या कोई कर लगाने से इनकार करने के खिलाफ हो, तो यह धारा 84 की उपधारा (1) के तहत अपील का मामला होगा, लेकिन जहां शिकायत यह है कि कर उस पर लगाया गया है जो कर योग्य नहीं था, तो यह करधान के मामले में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने का मामला होगा। अब, क्या छूट है और इसलिए कर योग्य नहीं है और जिसे वैधानिक कटौती के रूप में अनुमति दी गई है और इसका

हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है, इसके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

वह राशि जिस पर कर लगाया जाना है। सार रूप में परिणाम एक ही आता है। इसलिए वर्तमान मामले में सिविल कोर्ट के पास आवेदकों के दावे की सुनवाई करने का अधिकार था, यदि यह सच है, क्योंकि प्रतिवादी नगर पालिका ने 1911 के पंजाब अधिनियम 3 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है क्योंकि उसने आवेदकों की संपत्ति पर करों के आकलन और लेवी के संबंध में अधिनियम की धारा 3 (एल) (बी) (ii) को प्रभावी नहीं किया है। इस दृष्टिकोण में इस संशोधन आवेदन को सफल होना है।

उपरोक्त कही गई किसी भी बात का मुकदमे में प्रतिवादी नगरपालिका द्वारा किए गए किसी अन्य बचाव पर कोई असर नहीं पड़ता है। अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के अलावा, प्रतिवादी नगर पालिका के दो अन्य बचावों का भी संदर्भ दिया गया है। सीमा की रक्षा सहित अन्य बचाव हो सकते हैं। ये सभी पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर सवाल हैं, जिन पर कानून के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित समय पर ध्यान दिया जाएगा।

जिन परिस्थितियों में इस संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को उलट दिया जाता है और मामले को इस निष्कर्ष पर कानून के अनुसार परीक्षण के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया जाता है कि आवेदकों के दावे की सुनवाई करने का अधिकार उसके पास है, क्योंकि प्रतिवादी नगर पालिका ने 1911 के पंजाब अधिनियम 5 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। आवेदकों की संपत्ति पर करों का आकलन और वसूली। इस आवेदन में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है। पक्षकारों को उनके वकील के

माध्यम से 6 जून, 1967 को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram,
हरियाणा